

भारतीय मध्यस्थता के भविष्य को लेकर विशेषज्ञों में हुई गंभीर चर्चा

● यूपीईएस स्कूल ऑफ लॉ ने 'एडाप्ट या पेरिश' कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन

भास्कर समाचार सेवा

नई दिल्ली। यूपीईएस स्कूल ऑफ लॉ द्वारा प्रतिष्ठित कानूनी सम्मेलन श्रृंखला 'एडाप्ट या पेरिश' के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम रही भारतीय मध्यस्थता एक दोराहे पर: सुधार, विरोध और एक मध्यस्थता केंद्र के रूप में भविष्य, जिसके तहत भारत के शीर्ष न्यायविदों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एवं अध्यक्ष इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हेमंत गुप्ता द्वारा मुख्य भाषण दिए गए। इसके बाद हुई राउंडटेबल चर्चाओं और पैनल



पैनल डिसकशन में प्रतिभाग करते न्यायविद, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों।

सत्रों में भारत की मध्यस्थता प्रणाली के सामने खड़ी संरचनात्मक और सांस्कृतिक चुनौतियों को लेकर व्यापक संवाद हुआ। सम्मेलन में भारत का बदलता मध्यस्थता रुख, प्रक्रिया में विलंब, मध्यस्थों की जवाबदेही, नैतिकता व स्वायत्तता, न्यायिक हस्तक्षेप, प्रवर्तन की चुनौतियाँ और भारत का मध्यस्थता हब बनने का भविष्य। यह संवादात्मक मंच

विभिन्न पक्षों को एक साथ लाकर भारत में विश्वस्तरीय और आधुनिक मध्यस्थता व्यवस्था की दिशा में व्यावहारिक सुझावों और समाधान की तलाश में अहम साबित हुआ। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए डीन यूपीईएस स्कूल ऑफ लॉ डॉ. अभिषेक सिन्हा ने कहा कि भारत इस समय मध्यस्थता की दिशा में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।

'एडाप्ट या पेरिश' जैसे आयोजनों के माध्यम से हम विचारशील और क्रियाशील लोगों को एक मंच पर लाकर सिस्टम की खामियों पर चर्चा और सुधार की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। वर्षों से यूपीईएस स्कूल ऑफ लॉ ने टेक्नोलॉजी-संचालित उत्कृष्ट विधिक शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहां भारत की पहली एआर-वीआर लीगल लैब और

एआई-आधारित डिजिटल लॉ प्रोफेसर 'एबीएसआईएन' जैसे अनूठे प्रयोग किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड सरकार के सेतु आयोग के सहयोग से पब्लिक लॉ एंड पॉलिसी लैब की स्थापना भी की गई है, जहां छात्र प्रत्यक्ष रूप से नीतिगत और विधिक सुधार परियोजनाओं से जुड़ते हैं। वीडियो लीगल वर्ल्ड द्वारा नॉर्थ जोन में तीसरा और एनआईआरएफ 2024 रैंकिंग में भारत में 28वां स्थान प्राप्त करने वाला यूपीईएस स्कूल ऑफ लॉ आज देश का एक अग्रणी विधि शिक्षा संस्थान बन चुका है। किंग्स कॉलेज लंदन, यूसी बर्कले और यूएनएसडब्ल्यू सिडनी जैसे विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के साथ छात्रों को समकालीन कानूनी कौशल प्रदान करते हैं। 'एडाप्ट या पेरिश' जैसे प्रयासों के जरिए स्कूल ऑफ लॉ न केवल कानूनी विमर्श को दिशा दे रहा है, बल्कि आने वाले समय के लिए एक सशक्त, जागरूक और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले विधि विशेषज्ञों को तैयार कर रहा है।